

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ (राज0)

अनवानी आशारांनी बनाम जल्लाराम

मु.न. 215/2014


विषय मुख्यतः धारा 8(2) राज.उप.अधिनियम

हुक्म कार्यवाही विवरण

पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री इन्द्राज गोदारा व राज पैरोकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन किया कि चक 4 जे.आर.के. प.न. 94/244 कि. न. 1 ता 5 में दर्ज राजस्व रिकार्ड गै.मु. रास्ते को निरस्त किया जाकर प्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। यह कि इस रास्ता की किसी को आवश्यकता ना होने से यह रास्ता कभी धालू नहीं रहा है। उक्त रास्ता को निरस्त किया जाकर प्रार्थी के नाम उक्त गै.मु. भूमि को मुमकिन दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे।

राज पैरोकार द्वारा दौरान बहस प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए भविष्य में रास्ते की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना स्वारिज करने हेतु निवेदन किया। समाप्त बहस का मबन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्त मानवीय राजस्व मण्डल अजमेर के क्रम सं. 1 रुपनारायण के विधिक प्रतिबन्धि बनाम राज्य 1992 आर.आर.डी 496, क्रम सं. 2 शंकरसिंह बनाम गोगीदेवी आर.बी.जे (20) 2013 पेज 309, क्रम सं. 3 रमेश चंद बनाम मोहरसिंह आर.आर.टी. 2018(1) पेज 592 का न्यायिक मस्तिक से अध्ययन किया व बाद अध्ययन पाया कि शर्त संख्या 8 (2) 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी रास्ता स्वीकृत कर सकता है, परन्तु गैर मुमकिन रास्ता को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

धारा 88 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार सड़क तथा समस्त भूमि जो अन्य किसी की सम्पत्ति नहीं है वह राज्य सरकार की सम्पत्ति है। प्रश्नगत रास्ता राज्य सरकार का है। इसको निरस्त करवाने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (6) के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। गैर मुमकिन रास्ता सामान्यजन के उपयोग तथा उपभोग हेतु राज्य सरकार की सम्पत्ति है। जिसकी मालिक राज्य सरकार है। जिसमें सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग में किसी भी प्रकार से कोई बाधा अथवा अड़चन पैदा नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त न्यायायिक दृष्टान्तों की अनुसरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं के कारण इसी स्तर पर स्वारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर  की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक क्लर्क
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ